



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62814

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10197 वर्ष 2026

मुकीम

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बसदेव निषाद, रमा पति निषाद

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बसदेव निषाद और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रामकुमार वर्मा की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

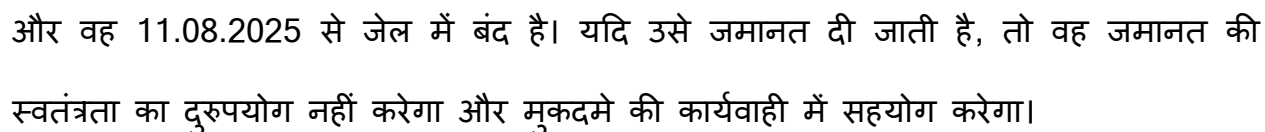
अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 237/2025, धारा 8/21 के तहत, पुलिस स्टेशन मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 120 ग्राम स्मैक पाउडर आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। कोई रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी आरिफ को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आवेदन संख्या 35314 2025 दिनांक 12.11.2025 के आदेश के अनुसार। इसलिए, आवेदक, जिसकी भूमिका समान है, समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने तीन मामलों में अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मुकीम** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। स्वयं प्रेरित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय के संबंध में, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।

25 मार्च, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।